



ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया: भारत का डिजिटल परिवर्तन

प्रलम्ब के लिये:

[डिजिटल बैंकिंग](#), [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम](#), [एकीकृत भुगतान इंटरफेस \(UPI\)](#), प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDSA), [आयुषमान भारत डिजिटल मशिन](#), [तत्काल भुगतान सेवा](#), [प्रीपेड भुगतान उपकरण \(PPI\)](#), [आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली \(AePS\)](#), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC), [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023](#)

मेन्स के लिये:

भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव, भारत के डिजिटल भुगतान का वर्तमान परिदृश्य, डिजिटल परिवर्तन के लिये भारत का वैश्विक दृष्टिकोण

प्रसंग:

830 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से जुड़ा लोकतंत्र है। हाल के वर्षों में डिजिटल लेन-देन कई गुना बढ़ गया है, जिससे भारत वास्तविक समय डिजिटल भुगतान में नरविवाद अग्रणी बन गया है।

स्मार्टफोन और कफियाती मोबाइल डेटा योजनाओं को व्यापक रूप से अपना आदिने भी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। ई-कॉमर्स, मोबाइल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा व्यवसाय कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

भारत में डिजिटल परिवर्तन की गति:

- भारत का डिजिटल परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है, बेहतर कनेक्टिविटी और तकनीकी क्षमताओं के चलते इसके नागरिकों की डिजिटल तक पहुँच और समावेशता में वृद्धि हुई है।
- [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम](#), [प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान \(PMGDSA\)](#) और [यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस \(UPI\)](#) आदि जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- दूरसंचार विकास योजना, [आकांक्षी जला योजना](#) और [वामपंथी उग्रवाद](#) से प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई जैसी कुछ पहलों ने पूरे भारत में पहुँच, कनेक्टिविटी, सामर्थ्य और समावेशता में सुधार किया है।
- [कॉमन सर्विस सेंटर \(CSC\)](#) जैसी पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों को [ई-गवर्नेंस](#), शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बैंकिंग जैसी सेवाएँ प्रदान की हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, डिजिटल सेवाएँ प्रदान करना और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है।
- देश भर में समरपति डिजिटल ड्राइव के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट उपभोक्ता में 150% की वृद्धि हुई है।
 - ऑकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-2021 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 95.76 मिलियन इंटरनेट ग्राहक जुड़े, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 92.81 मिलियन रही।
- इस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किये गए डिजिलॉकर में 16 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इससे उपयोगकर्ता किसी भी दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से साझा तथा एक्सेस कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान:

- PMGDSB को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और यह ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है।
- PMGDSB के परिणामस्वरूप पूरे भारत में पहुँच, कनेक्टिविटी, सामर्थ्य और समावेशिता में सुधार हुआ है।
- इसने 5.96 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है और 4.44 करोड़ छात्रों को डिजिटल साक्षरता में प्रमाण पत्र प्रदान किया। यशशिव का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है जिसके तहत अब तक 6.92 करोड़ उम्मीदवार पंजीकृत हो चुके हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव:

- **स्वास्थ्य देखभाल:**
 - डिजिटल तकनीक ने देश में विश्व के सबसे बड़े और सबसे कुशल **कोविड-19 टीकाकरण** कार्यक्रम को चलाने में मदद की।
 - **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** और **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य बलूपरि** स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने में सहायक रहे हैं।
 - चाहे वह **टेलीमेडिसिन** हो, AI-सक्षम चिकित्सा उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हो, डिजिटल तकनीक तेज़ी से भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों में अपनी पैठ बना रही है।
 - **आयुषमान भारत डिजिटल मिशन** जैसी पहल ने भारत में स्वास्थ्य प्रणालियों के डिजिटलीकरण की गति को और तेज़ कर दिया है।
 - प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समग्र रूप से सक्रियता के साथ और अधिक नागरिक-केंद्रित होती जा रही है।
- **पर्यटन:**
 - एक अन्य क्षेत्र जिसमें डिजिटल क्रांति के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया, वह है पर्यटन और देशाटन।
 - इंटरनेट ने लोगों के **अन्वेषण, योजना बनाने और यात्रा का अनुभव करने के तरीके** में क्रांतिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - ऑनलाइन बुकिंग से लेकर **वर्चुअल टूर और यात्रा सामग्री निर्माण तक इंटरनेट यात्रियों के लिये एक अनिवार्य उपकरण** बन गया है।
- **व्यवसाय:**
 - डिजिटल भुगतान ने भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाकर परिचालन कार्यों में कमी करके और उत्पादकता में वृद्धि कर व्यवसायों को रूपांतरित कर दिया है।
 - तेज़ी से बढ़ते डिजिटल भुगतान परदृश्य ने भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में बदलाव ला दिया है।
 - वर्तमान में व्यवसाय समय और धन दोनों की बचत करने में सक्षम हैं, साथ ही अपनी मुख्य दक्षताओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह डिजिटल भुगतान विकल्पों की पेशकश से संभव हुआ है, जो उन्हें **बड़े बाज़ार में प्रवेश करने तथा नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है।**

भारत में डिजिटल भुगतान का वर्तमान परदृश्य:

- **भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति:**
 - डिजिटल बुनियादी ढाँचे के तेज़ी से वसितार के परिणामस्वरूप भारत के भुगतान परदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।
 - वित्तीय लेन-देन **मॉडल में डिजिटल भुगतान की ओर एक प्रभावशाली बदलाव देखा गया है**, जिससे डिजिटल भुगतान को अत्यधिक महत्त्व देकर बढ़ावा देने से आधुनिक डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
 - पछिले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान लेन-देन में **अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।** उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा सुविधाजनक डिजिटल भुगतान वधियाँ जैसे:
 - भारत **इंटरफेस फॉर मनी- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (BHIM-UPI)**, तत्काल भुगतान सेवा (**IMPS**), **प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI)**, **आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)** और **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)** ने व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों को भुगतान की सुविधा प्रदान करके डिजिटल भुगतान परदृश्य में क्रांति लाते हुए पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है।
- **वैश्विक डिजिटल भुगतान में UPI अग्रणी:**
 - भारत वर्ष 2022 में 89.5 मिलियन लेन-देन के साथ डिजिटल भुगतान में दुनिया में अग्रणी है और UPI एक क्रांतिकारी उत्पाद के रूप में उभर रहा है। **ऑकड़ों के अनुसार, वैश्विक वास्तविक समय पर भुगतान में भारत का हिस्सा वार्षिक रूप से 46% था।**
 - इस सूची में **ब्राज़ील दूसरे स्थान पर** था, उसके बाद चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया थे।
 - तेज़ी से वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि भारत में डिजिटल भुगतान लेन-देन **अन्य चार प्रमुख देशों की तुलना में अधिक है।**
 - UPI लेन-देन वर्ष 2025 तक प्रतिदिन 1 बिलियन तक पहुँचने की ओर अग्रसर है, जो देश में खुदरा डिजिटल भुगतान का 90% हिस्सा है।
- **पारंपरिक भुगतान वधियाँ:**
 - डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)**, और **रयिल टाइम ग्रांस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)** जैसी पारंपरिक भुगतान वधियाँ का तेज़ी से वसितार हुआ है।

नोट:

- फरवरी 2023 में भारत के UPI और सगिापुर के PayNow को दोनों देशों के बीच तेज़ी से **प्रेषण** सुनिश्चित करने के लिये एकीकृत किया गया

भारत द्वारा डजिटल युग में डेटा संरक्षण के प्रयास:

- भारत ने डजिटल दुनिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये लैंडमार्क **डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** पारित किया है।
- वधियक का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा को दुरुपयोग से बचाना और वैश्विक तकनीक-आधारित निवेश के प्रवाह को सक्षम करना है, जिससे इस क्षेत्र को **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने की दशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख चालक बनाया जा सके।
- यह वधियक भारत की डजिटल विकास यात्रा में एक नए युग की शुरुआत करता है, जो वर्तमान की विश्व स्तर पर परस्पर जुड़ी डजिटल अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत डेटा की उपयोगिता और केंद्रीयता को पहचानता है और ऐसे व्यक्तिगत डेटा को दुरुपयोग से बचाने की आवश्यकता का भी संज्ञान लेता है।

डजिटल परिवर्तन हेतु भारत का वैश्विक दृष्टिकोण:

- भारत की डजिटल परिवर्तन यात्रा ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है, जिससे टिकाऊ, सस्ती और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी के लिये डजिटल पहुँच, सेवाओं की डजिटल डिलीवरी और डजिटल समावेशन सुनिश्चित हुआ है।
- इस परिवर्तन को शेष विश्व में आगे बढ़ाते हुए भारत ने **G20** में एक शासन ढाँचे और **डजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी देशों के लिये समान रूप से सुलभ हो।
- विकास के लिये डेटा भारत की **G20 अध्यक्षता** के दौरान "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" यानी वसुधैव कुटुंबकम के समग्र वषिय का एक अभिन्न अंग है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2022)

1. आरोग्य सेतु
2. कोवनि
3. डजिलॉकर
4. दीकषा

उपर्युक्त में से कौन-से ओपन-सोरस डजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनयिों का गठन, जैसा की चीन ने किया।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े ऑकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनयिों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुवधि प्रदान करना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न: कभी-कभी समाचारों में देखने वाले 'डिजिलॉकर' के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सॉफ्टवेयर है।
2. यह आपके ई-दस्तावेजों तक आपकी पहुँच को संभव बनाता है चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति किहीं भी हो।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अवभाज्य अंग बनाने में पहल की"। चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/transforming-india-india-s-digital-transformation>

